

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3026
जिसका उत्तर 21 दिसंबर, 2023 को दिया जाना है।

.....

बुन्देलखंड में जल संरक्षण

3026. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त बुन्देलखण्ड क्षेत्र, विशेषकर पन्ना, कटनी और छतरपुर जैसे आकांक्षी जिलों में जल संरक्षण और स्थिरता के लिए प्रयास किए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) से (ग): जल राज्य का विषय है, इसके संरक्षण और स्थायित्वता सहित जल संसाधनों से संबंधित सभी मामले मुख्यतः राज्यों की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार द्वारा तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान की जाती है। जल संरक्षण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। मध्य प्रदेश के सूखा प्रवण बुंदेलखंड क्षेत्र सहित पूरे देश में जल संरक्षण और इसकी स्थिरता के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं:

(1) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा पन्ना, कटनी और छतरपुर जिलों को शामिल करते हुए मध्य प्रदेश राज्य में 2.69 लाख वर्ग किमी सहित और पूरे देश के संपूर्ण मैपिंग योग्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (एनएक्यूआईएम) परियोजना पूरी कर ली गई है। जलभृत मानचित्र और प्रबंधन योजनाएं तैयार कर कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य एजेंसियों को उपलब्ध कराई गई हैं। ये रिपोर्ट (सीजीडब्ल्यूबी - प्रकाशन और मीडिया वेयरहाउस) पर भी उपलब्ध हैं। प्रबंधन योजनाओं में पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से विभिन्न जल संरक्षण उपाय शामिल हैं। इसके साथ ही, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा जल संरक्षण सहित भूजल और इसके प्रबंधन के विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीजीडब्ल्यूबी द्वारा कटनी, छतरपुर और पन्ना जिलों (छतरपुर जिले में 6, पन्ना जिले में 1 और कटनी जिले में 1) में कुल 8 जन-संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके साथ ही सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल पेशवरों के लिए छतरपुर जिले में 2 टियर II प्रशिक्षण कार्यक्रम और 6 टियर-III प्रशिक्षण कार्यक्रम, अर्थात् छतरपुर जिले में 5 और पन्ना जिले में 1 का भी आयोजन किया गया है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए एक मास्टर प्लान -2020 तैयार किया गया है जो अनुमानित

लागत सहित देश की विभिन्न भू-स्थितियों के लिए अलग-अलग संरचनाओं को दर्शाते हुए एक मैक्रो स्तरीय योजना है। मास्टर प्लान में मध्य प्रदेश में लगभग 7.2 लाख संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। मास्टर प्लान के तहत, छतरपुर जिले को पायलट आधार पर मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए चुना गया है, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा अब तक 719 कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया गया है।

(2) जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वार्षिक आधार पर वर्ष 2019 से जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कोविड महामारी के कारण वर्ष 2020 में जेएसए का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका। चालू वर्ष में दिनांक 04.03.2023 को जेएसए की श्रृंखला में चतुर्थ जल शक्ति अभियान: कैच द रेन 2023, का शुभारंभ भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा "पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता" विषय के साथ देश के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी) में कार्यान्वयन के लिए किया गया है, इसमें मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिले पन्ना, कटनी और छतरपुर शामिल हैं। वर्ष 2021 से 2023 तक जेएसए: सीटीआर के अंतर्गत मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिलों पन्ना, कटनी और छतरपुर सहित मध्य प्रदेश राज्य में पूरे किए गए कार्यों का ब्यौरा **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

(3) भारत सरकार द्वारा समुदाय आधारित स्थायी भूजल प्रबंधन के माध्यम से भूजल स्तर में गिरावट को रोकने के उद्देश्य से सात राज्यों अर्थात् गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों के 229 ब्लॉकों के अंतर्गत 8213 ग्राम पंचायतों (जीपी) के चिन्हित जल की कमी वाले क्षेत्रों में एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना अटल भूजल योजना (अटल जल) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना का कार्यान्वयन दिनांक 01.04.2020 से 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जा रहा है। जल बजट और प्रस्तावित मांग पक्ष के उपायों जैसे सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, पाइपलाइनों के उपयोग आदि और वर्षा जल संचयन संरचनाओं जैसे चेक डैम, फार्म तालाब, रिचार्ज शाफ्ट और अन्य कृत्रिम पुनर्भरण/जल संरक्षण संरचनाओं सहित आपूर्ति पक्ष के उपायों वाली ग्राम पंचायत-वार जल सुरक्षा योजनाएं (डब्ल्यूएसपी) चालू स्कीमों के अभिसरण के माध्यम से तैयार और निष्पादित की जाती हैं।

(4) सरकार वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन कर रही है, जिसका उद्देश्य खेत पर जल की प्रत्यक्ष पहुँच में वृद्धि और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, कृषि जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं की शुरुआत आदि है। सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) योजना के तहत, 1817.39 करोड़ रुपये की 276 एसएमआई योजनाएं शामिल की गईं, जिनमें पन्ना जिले की 24 योजनाओं को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार को 987.69 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है और 29.75 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। इसके अतिरिक्त, जल निकायों (डब्ल्यूबी) की मरम्मत, पुनरुद्धार और नवीकरण (आरआरआर) स्कीम के तहत, 183.24 करोड़ रुपये की लागत से डब्ल्यूबी स्कीम की 125 आरआरआर में पन्ना की 5 और कटनी जिले की 2 योजनाओं को शामिल किया गया है। मध्य

प्रदेश राज्य सरकार को 37.70 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है और 11.00 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।

(5) सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस) का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसमें प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित लोक कार्यों के लिए प्रावधान हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ देश में जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाओं का निर्माण भी शामिल है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 (16.12.2023 तक) के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के अंतर्गत छतरपुर, कटनी और पन्ना के आकांक्षी जिलों सहित मध्य प्रदेश राज्य में पूरे किए गए जल संरक्षण और जल संचयन कार्यों और किए गए व्यय का जिला-वार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

अनुलग्नक-1

“बुन्देलखंड में जल संरक्षण” के संबंध में लोक सभा में दिनांक 21.12.2023 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3026 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक जेएसए के तहत मध्य प्रदेश राज्यों में पूरा किया गया कार्य: सीटीआर

जल शक्ति अभियान : कैच द रेन								
राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय								
कार्यकलाप-वार स्थिति रिपोर्ट, मध्य प्रदेश (दिनांक 22.03.2021 से 15.12.2023 तक की स्थिति)								
क्रम संख्या	वर्ष	जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन	पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण	पुनः प्रयोग और पुनर्भरण संरचना	वाटरशेड विकास	गहन वनरोपण	प्रशिक्षण कार्यक्रम/ किसान मेले	
1.	2023	36487	7031	15751	39284	15422	15	
2.	2022	229649	6942	25909	65403	512076	1297	
3.	2021	106484	3812	19225	97822	1513665	2805	
Total		372620	17785	60885	202509	2041163	4117	
कुल जल संबंधित कार्य		6,53,799						

क्र.सं.	जिले का नाम	*जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन	*पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण	*पुनः उपयोग और पुनर्भरण संरचनाएँ	*वाटरशेड विकास	*सघन वनीकरण	प्रशिक्षण कार्यक्रम/किसान मेले
1	छतरपुर-2023	2521	125	545	2529	211	0
	छतरपुर-2022	1822	78	620	2682	4425	16
	छतरपुर-2021	2828	72	235	3240	10305	41
	कुल	7171	275	1400	8451	14941	57
2	कटनी-2023	488	173	404	929	125	0
	कटनी-2022	854	121	1812	3023	181	11
	कटनी-2021	1210	181	520	3668	15852	43
	कुल	2552	475	2736	7620	16158	54
3	पन्ना -2023	528	264	89	544	261	0
	पन्ना -2022	850	152	262	2440	895	0
	पन्ना -2021	758	69	47	1974	2554	43
	कुल	2136	485	398	4958	3710	43

“बुन्देलखंड में जल संरक्षण” के संबंध में लोक सभा में दिनांक 21.12.2023 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3026 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 (16.12.2023 तक) के दौरान महात्मा गांधी एनआरईजीएस के तहत मध्य प्रदेश राज्य में पूरे किए गए जल संरक्षण और जल संचयन कार्यो और किए गए व्यय का जिलावार ब्यौरा			
क्रम संख्या	जिला	पूरे किए गए	
		कार्यो की संख्या	व्यय (लाख रुपये)
1	छतरपुर	2279	2460.29
2	दमोह	764	2453.83
3	दतिया	391	269.95
4	पन्ना	766	1568.63
5	सागर	775	472.77
6	टीकमगढ़	1640	704.3
1	कटनी	913	1321.89
